LATEST

NEWS

Election

Date : 20th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर

जयपुर 20-01-2026

एसआईआर • कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने, दोनों ने दिल्ली जाकर लगाए आरोप

हमारे सपोर्टर्स के बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, हम कोर्ट जाएंगे : डोटासरा

जयपुर | एसआईआर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराया। दोनों ने कहा कि जब बीएलओ सुसाइड कर रहे थे तब मतदाता नाम जोड़ने, काटने की तिथि क्यों नहीं बढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद तिथि क्यों बढ़ा कर 15 की जगह 19 जनवरी की? हमें भाजपा के 10 बीएलए ने लिखकर दिया है कि हमने फॉर्म जमा नहीं करवाया। हमारे नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस घपले के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट में जाएगी और हम जगह जगह मुकदमे दर्ज कराएंगे।

दोनों ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस विचारधारा के वोटर्स के नाम कटवाने

के लिए प्रिंटेड फॉर्म-7 एसडीएम, तहसीलदार और जिला कलक्टर के यहां पहुंचा दिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में 45 लाख वोट काटने की सिफारिश की गई है। 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई, लेकिन 3 जनवरी को भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए और एजेंडा सेट किया कि कांग्रेस समर्थकों के नाम कैसे हटाएं? 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक भाजपा के 937 बूथ लेवल एजेंट ने 211 नाम जोड़ने और 5994 नाम काटने का आवेदन किया। कांग्रेस के 110 बूथ लेवल एजेंट ने 185 फॉर्म जोड़ने और दो नाम हटाने का आवेदन किया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी है। लेकिन 13 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आते हैं और 4 घंटे भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करते हैं। उसके बाद गुप्त रूप से फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार पहुंच जाते हैं।

फॉर्म की फोरेंसिक जांच हो

नेता प्रतिपक्ष जूली ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जितने भी प्रिंटेड फॉर्म राजस्थान में आए हैं, उन सबकी फोरेंसिक जांच हों। फॉर्म कहां छपे और कौन इन्हें जयपुर लाया? ये सभी फॉर्म एक ही जगह छापे हैं। छापने के बाद जयपुर भेजे गए। इसकी जांच होनी चाहिए।

इधर... राठौड़ बोले- अफवाह फैला रहे हैं कांग्रेसी नेता

जयपुर/नई दिल्ली | भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि डोटासरा का यह स्वभाव बन चुका है कि वे बिना तथ्य और प्रमाण के मनगढ़ंत बातें करें और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करें। अफवाह फैलाना और अनर्गल बयानबाजी करना अब उनकी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी यह प्रक्रिया कई बार अपनाई गई है। वर्ष 1992 में एसआईआर हुआ, इसके बाद 2002, 2003 और 2004 में भी कई राज्यों में कांग्रेस सरकारों के दौरान मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया। ऐसे में आज इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और हर आपत्ति की विधिवत जांच की जाएगी।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 20 Jan 2026 - Page 5

डोटासरा-जुली ने लगाए गड़बड़ियों के आरोप

SIR पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

भाजपाध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया पलटवार

नवज्योति ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सोमवार को राजधानी दिल्ली में भाजपा एवं कांग्रेस आमने सामने हो गए। सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर गड़बड़ियां करने के गंभीर आरोप लगाए। तो शाम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इन आरोपों पर पलटवार किया।

कांग्रेस मतदाताओं के नाम कटवा रही भाजपा : डोटासरा

एआईसीसी मुख्यालय में डोटासरा एवं जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया

कि भाजपा द्वारा सरकारी मशनरी पर दबाव बनाकर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही थी। लेकिन बीएल संतोष के हालिया जयपुर दौरे के बाद अचानक गड़बड़ियों की शुरूआत हुई। हर विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 20 हजार मतदाताओं के फर्जी नाम जुड़वाने एवं कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के कटवाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए हैं। वहीं, नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में हजारों नाम काटने के आवेदन दिए गए हैं। जिसे वह विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाएंगे।

कांग्रेस घुसपैठियों का नाम जुड़वाना चाहती है: मदन राठौड़

वहीं, भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा बेबुनियाद एवं गुमराह करने

वाले आरोप लगा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने जबरन भाजपा के केन्द्रीय नेताओं पर आरोप लगाए हैं। जिसकी वजह से उन्हें आज यहां जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा है। राठौड़ ने कहा कि देश में पहले भी एसआइआर हुआ है। जिन मतदाताओं के नाम साल 2002 की सूची में हैं। उनका कोई नाम नहीं काट सकता। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस घुसपैठियों नाम मतदाता सूचियों में जुड़वाना चाहती है। जो किसी भी हाल में हो नहीं सकता। इस देश का नागरिक ही वोटर हो सकता है। बाकी कोई नहीं। यही परेशानी कांग्रेस की है। इसीलिए कांग्रेस नेता गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि डोटासरा के पास यदि कोई प्रमाण है, तो विधानसभा में पेश करें। राज्य सरकार तथ्यों के साथ उनका जवाब देगी।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 20 Jan 2026 - Page 11

पूर्व पार्षद ने थाने में दी शिकायत, मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश का आरोप

नवज्योति,जयपुर। एआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की शिकायत पूर्व पार्षद ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने की कथित साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वार्ड संख्या 89 से पूर्व पार्षद अकबरद्दीन ने पुलिस थाना लालकोठी में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया कि उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के उद्देश्य से फर्जी और कूटरचित फॉर्म-7 भरकर झूठी घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि उनका नाम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र 53 के वार्ड 89, बूथ संख्या 107 सांगानेरी गेट की मतदाता सूची में क्रम संख्या 692 पर दर्ज है तथा उन्हें एपिक नंबर एमसीएम 3202645 जारी है।

एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन्होंने नियमानुसार बीएलओ को परिगणना प्रपत्र जमा करा दिया था। इसी दौरान 15 जनवरी, 2026 को बीएलओ पुष्पा ने उन्हें सूचना दी कि अशोक नामक व्यक्ति ने उनके नाम, मकान नंबर और एपिक नंबर का उपयोग करते हुए फॉर्म-7 जमा कराया है। इस फॉर्म में यह गलत घोषणा की गई कि अकबरद्दीन उक्त पते से स्थानांतरित हो चुके हैं। अकबरद्दीन ने शिकायत में स्पष्ट किया कि वे पिछले 50 वर्षों से उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहे हैं।

पंजाब केसरी
TUE,20 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

एसआईआर पर रार

कांग्रेस ने लगाया वोट चोरी करने का आरोप तो जवाब में भाजपा ने कहा- अर्नगल बयानबाजी करना कांग्रेस की राजनीति का अब स्थाई हिस्सा

'राजस्थान में 45 लाख लोग अबसेंट, शिफ्टेड व डेथ'

पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा 1.40 लाख फार्म रजिस्टर, हो फॉरेंसिक जांच

डोटासरा-जूली ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जड़े आरोप, जहां कांग्रेस जीती वहां गड़बड़ी

जयपुर, 19 जनवरी (विशेष संवाददाता): एसआईआर प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह भाजपा व चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर सोमवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर जमकर आरोप लगाए। दोनों ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब हैं। भाजपा वोट चोरी कर रही है। इन सभी 45 लाख लोग अबसेंट, शिफ्टेड व डेथ पाए गए हैं। इस मामले की फॉरेंसिक जांच हो।

डेढ़ लाख फार्म रजिस्टर

पीसीसी चीफ डोटासरा व जूली ने बताया कि झुंझुनू में एक दिन में नाम काटने के लिए 13 हजार 882 फार्म 7 लिए गए। वहीं मंडावा में एक दिन में 16 हजार 276 फार्म तो उदयपुरवाटी में 1241 एवं खेतड़ी में 1478 फॉर्म लिए गए। अभी तक करीब 1 लाख 40 हजार फार्म तो रजिस्टर भी करवा दिए गए है।

डोटासरा ने कहा कि जिन 45 लाख लोगों को अबसेंट, शिफ्टेड व डेथ (एएसडी) बताया गया वह यानि वे जब तक प्रमाण नहीं दिखाते, वोट नहीं दे सकते। नियम ये कहता है कि अगर इनमें से किसी का नाम जुड़वाना है, तो दस्तावेजों के साथ जुड़वाया जा सकता है। वहीं 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो जाने के बाद उनका नाम काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। उन्होंने आगे कहा कि 3 जनवरी तक कोई अफरा-तफरी नहीं थी, सारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा था। 3 जनवरी को भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष राजस्थान गए और वहां बैठक की। इसके बाद फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और वोट काटने का काम शुरू हुआ।

डोटासरा ने बताया कि मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया एक डेटा आपसे साझा कर रहा हूं। इसमें बताया गया है कि भाजपा ने 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक 937 बीएलए के माध्यम से 211 नाम जोड़ने और 5694 वोट काटने का आवेदन दिया है। वहीं कांग्रेस ने 110 बीएओ के माध्यम से 185 नाम जोड़ने व 2 नाम हटाने का आवेदन दिया है। डोटासरा ने कहा कि हमने पहले ही आशंका जताई थी कि भाजपा व चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस की विचाराधारा के लोगों का नाम काटने के लिए डेट को आगे बढ़ाएंगे और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। डोटासरा ने कहा कि मैंने अपनी विधानसभा में 627 फार्म दिए जब दोबारा 2 हजार फार्म लेकर गए तो एसडीएम ने मना कर दिया।

इन मुद्दों को भी उठाया

- कांग्रेस ने एक बीएलओ एक दिन में 10 फार्म दे सकता है लेकिन इसका पालन नहीं किया गया
- भाजपा विधायक, मंत्री व विधायक प्रत्याशियां ने बीएलए के फर्जी साइन कर हजारों फार्म एसडीएम के यहां जमा कराए
- कई बीएलओ ने मीडिया के सामने आकर बाइट दी कि फार्म पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, फर्जी हस्ताक्षर किए गए, फार्म अधूरे हैं, तो कई पर मोबाइन नंबर भी नहीं डाले गए
- चुनाव आयोग से लेकर फील्ड व ऑफिसों के अधिकारियों पर प्रेशर
- भाजपा विधायक खुद ही नाम काटने के हजारों फार्म जमा करवा रहे हैं, पूछने पर कहते कि बांग्लादेशी-रोहिंग्या के नाम कटवा रहे, इसकी जांच हों
- जिन सीटों पर कांग्रेस 1 व 2 हजार वोट या नजदीकी चुनाव जीती वहां गड़बड़ी हो रही

13, 14 व 15 जनवरी को सर्वाधिक कटे नाम

डोटासरा ने कहा कि अमित शाह 13 तारीख को राजस्थान जाते हैं, सीएमआर में रुकते हैं। फिर 3 से 13 तारीख के बीच भाजपा में गुप्त रूप से खेला चलता है। हर विधानसभा में 10-15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म प्रिंट होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। 13, 14 और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों फॉर्म देकर नाम काटे जाने का आंकड़ा है। ये काम विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर किया जाता है जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। इतना ही नहीं कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम काटे जाने के फॉर्म दिए गए।

राठौड़ का वार- डोटासरा बिना तथ्यों के फैलाते हैं भ्रम

एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता

जयपुर,19 जनवरी (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि डोटासरा का यह स्वभाव बन चुका है कि वे बिना तथ्य और प्रमाण के मनगढ़ंत बातें करें और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करें। अफवाह फैलाना और अनर्गल बयानबाजी करना अब उनकी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गया है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में भी यह प्रक्रिया कई बार अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में एसआईआर हुआ, इसके बाद 2002, 2003 और 2004 में भी विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारों के दौरान मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया। ऐसे में आज इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

राठौड़ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल और केवल यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाए। इसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग या मजहब का कोई भेदभाव नहीं होता। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह कार्य करता है। आयोग का एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, न कि किसी राजनीतिक दल को लाभ या हानि पहुंचाना। राठौड़ ने कहा कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची से हटाने में क्या दिक्कत है। जो लोग जीवित नहीं हैं या जिनका नाम दो जगह दर्ज है, उनके नाम क्यों न काटे जाएँ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और उसे अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है।

कांग्रेस के झूठे प्रचार व अफवाहों से सावधान रहें

राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार एसआईआर को लेकर झूठे आरोप गढ़ रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के नाम लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत हैं। राठौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रत्येक संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और जनता से अपील करती है कि कांग्रेस के झूठे प्रचार और अफवाहों से सावधान रहें। देश का लोकतंत्र मजबूत है और उसे कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे।

विधानसभा जाना नहीं चाहते डोटासरा

उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि अगर कांग्रेस को बहस करनी है तो वह विधानसभा में आए। हमारे दो साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से की जाए, हम बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा जाना नहीं चाहते और सदन का सामना करने से बचते हैं। बैरवा ने कहा कि जनता को गुमराह करने का प्रयास ठीक नहीं है, अगर किसी मुद्दे पर संवाद चाहिए तो सरकार जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं और 90 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस आमने-सामने बैठकर चर्चा करे, सरकार हर सवाल का जवाब देगी।

'एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानूनन, हर आपत्ति की होगी जांच'

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और हर आपत्ति की विधिवत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा फॉर्म जमा होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी फॉर्म की जांच होगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत वास्तविक मतदाता की ही पुष्टि की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा उन्हीं व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है, जिन्हें उसने स्वयं लागू किया था। ईवीएम कांग्रेस की ही देन है, लेकिन चुनाव हारते ही वही ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है। इससे पहले एसआईआर भी कांग्रेस के समय भी होता था, लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है।

डोटासरा व जूली ने भाजपा पर लगाया मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप

जयपुर (कासं)। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, भाजपा द्वारा राजस्थान में "धोखाधड़ी" के जरिए कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रही है। डोटासरा ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के बाद लगभग 45 लाख नाम "अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत" पाए गए, जिसके बाद 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष के राजस्थान दौरे के बाद अचानक फर्जी तरीके से नाम जोड़ने और हटाने का काम शुरू हो गया।

■ **दोनों कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रैस कॉफ्रैंस कर कहा कि "एस.आई.आर. के बहाने में राजस्थान में कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश चल रही है।"**

डोटासरा ने दावा किया कि, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 कंप्यूटरीकृत फॉर्म वितरित किए गए। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के फर्जी हस्ताक्षर वाले हजारों फॉर्म एस.डी.एम. को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, एक बीएलओ एक दिन में केवल 10 फॉर्म ही वितरित कर सकता है। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। कई बीएलओ ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर फर्जी है। डोटासरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 13 जनवरी के जयपुर दौरे को एक "गुप्त ऑपरेशन" बताया और आरोप लगाया कि, अमित शाह के दौरे के बाद मतदाता सूचियों में बदलाव की प्रक्रिया में तेजी आई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के नवीन महाजन से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर इन फर्जी फॉर्म्स को स्वीकार करने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी डोटासरा के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि, बीजेपी ने स्थानीय पदाधिकारियों को पेन ड्राइव में डेटा दिया है ताकि वे हर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों के नाम हटा सकें और बीजेपी समर्थकों के फर्जी नाम जोड़ सके।

कांग्रेस का फर्जीवाड़े का आरोप, भाजपा ने कहा-जांच से भागें नहीं

'शाह-संतोष के दौरे के बाद शुरू हुआ खेल'

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसआइआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर दौरे के बाद फर्जी वोट जोड़ने और नाम काटने का खेल शुरू हुआ।

डोटासरा और जूली ने यह बातें संयुक्त रूप से सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। डोटासरा ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार फर्जी कंप्यूटरीकृत फॉर्म प्रिंट कराए गए, जिन पर बीएलए के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। यह काम विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिह्नित कर किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। वहीं, जूली ने चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय से मांग की कि राज्य में जमा हुए सभी फॉर्म्स की फोरेंसिक जांच कराई जाए, यह पता लगाया जाए कि ये फॉर्म कहां छपे, किसने और कैसे इन्हें कार्यालयों तक पहुंचाया।

'बड़े नेताओं के नाम पर विवाद की कोशिश'

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एसआइआर से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डोटासरा भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के नाम लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि देश का प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटना चाहिए। इसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग या मजहब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि जो भी आपत्तियां की गई हैं उनकी जांच होगी और जो जांच में सही होगा वही नाम हटेगा। जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची से हटाने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं ने एसआइआर को लेकर न तो कोई बयान दिया है और न ही कोई चर्चा की है। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अगर कांग्रेस को बहस करनी है तो वह विधानसभा में आएं। दरअसल डोटासरा विधानसभा जाना नहीं चाहते।

18 जनवरी तक प्राप्त फॉर्मों का विवरण जारी

10.48 लाख मतदाताओं ने नाम जुड़वाने का किया दावा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य में एसआइआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। निर्वाचन विभाग की ओर बताया गया है कि एसआइआर के आधार पर तैयार मतदाता सूची में फिर से नाम जोड़ने के लिए 10.48 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, जबकि नाम कटवाने के लिए आए आवेदनों की संख्या 1.10 लाख है।

निर्वाचन विभाग की ओर से सोमवार को इस बारे में बुलेटिन जारी किया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इसमें शामिल आंकड़े 18 जनवरी की रात तक के हैं। निर्वाचन विभाग ने 16 दिसंबर को एसआइआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी। इसके अनुसार करीब 41.84 लाख से अधिक नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए। एसआइआर के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने तक नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,91,267 और नाम हटाने के लिए आए आवेदनों की संख्या 24,616 थी। विभाग की ओर से 19 जनवरी को जारी बुलेटिन के अनुसार नाम जोड़ने के लिए करीब 10,48,493 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि नाम हटाने के लिए आए आवेदनों की संख्या 1,10,474 बताई गई।

SC to EC: List Bengal voters with 'logical discrepancy'

10 More Days Granted For Furnishing Docus

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: As almost 1.4 crore Bengal voters face "logical discrepancy" notices requiring submission of documentary proof, Supreme Court ordered Election Commission (EC) on Monday to display the list of such people in panchayat and block offices, and gave them 10 days to furnish documents to establish their credentials for inclusion in the state electoral roll.

Given the size of work and incidence of violence against EC officials conducting the special intensive revision (SIR) of the electoral roll ahead of assembly elections in Bengal, a bench of CJI Surya Kant and Justices Dipankar Datta and Joymalya Bagchi asked the state to provide manpower as required by EC and directed the director general of police to ensure maintenance of law and order for smooth conduct of the drive.

Having two judges from West Bengal on the bench helped the court understand peculiarities associated with the state and appreciate arguments of senior advocate Kalyan Banerjee, who complained that EC is not accepting state board examination admit cards, in which only the date of birth of a person is recorded, as a documentary proof for age.

Justice Datta said since the state education board does not record the date of birth in the certificate issued after passing the examination, EC must consider the admit card as documentary proof. EC counsel Rakesh Dwivedi assured that the commission would take necessary corrective steps.

▶**Child marriage, P 6**

IN THE COURTS

- **Abusive language against an SC or ST person by itself not offence** under SC/ ST (Prevention of Atrocities) Act. Abuse has to be 'by caste name', in public view | **P 7**
- SC directs **MP govt to decide in 2 weeks on sanction to prosecute minister** Kunwar Vijay Shah for making remarks **targeting Col Sofiya Qureshi** after Sindoor
- Delhi HC **quashes 2016 income tax notices to NDTV founders** Prannoy & Radhika Roy, asks dept to **pay ₹1L each** to both for harassment | **P 7**
- Court **convicts man for 2018 murder bid though he did not use the weapon,** as common intent proved

BJP, EC colluded to delete voters: Cong

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Senior Rajasthan Congress members Monday accused the ruling BJP of large-scale tampering with electoral rolls in the state, alleging the involvement of Union home minister Amit Shah and BJP national general secretary B L Santosh, and claiming collusion with Election Commission officials during the Special Intensive Revision (SIR) process.

Addressing a press conference in New Delhi, Rajasthan Congress president Govind Singh Dotasra and Leader of Opposition Tikaram Jully said the draft voter list published after the SIR categorised around 45 lakh people as absent, transferred or deceased, with objections invited until Jan 15. Dotasra alleged that the process changed after Santosh's Rajasthan visit on Jan 3 and Shah's stay on Jan 13. He claimed that "fake, computer-generated forms" were printed constituency-wise and distributed, and that the deletion drive was accelerated between Jan 3 and 13, targeting constituencies where Congress had won.

TOI

Raj Cong chief Govind Singh Dotasra and LoP Tikaram Jully at a presser in New Delhi Monday

Citing Election Commission data, Dotasra said BJP's 937 Booth Level Agents (BLAs) submitted applications between Dec 17 and Jan 14 to add 211 names and delete 5,694 names, while Congress's 110 BLAs submitted applications to add 185 names and delete two. He further alleged that 10,000 to 15,000 computerised forms with forged BLA signatures were printed per assembly constituency.

Hindustan Times

SC flags voters' 'stress' in WB SIR; notice sent to EC

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Monday expressed concern over the "stress and strain" faced by ordinary voters who have received notices under the special intensive revision (SIR) of electoral rolls in West Bengal, as it issued a slew of directions to the Election Commission of India (ECI) and reminded the poll body that a core objective of the exercise was to ensure that no eligible voter is left out.

"See the strain and stress going on for ordinary people. Over one crore (10 million) people have been issued notices...we are going to pass some orders," observed the bench, led by Chief Justice of India Surya Kant, emphasizing that while corrective measures in electoral rolls were permissible, the process must be transparent and voter-friendly.

The bench, also comprising justices Dipankar Datta and Joymalya Bagchi, was hearing a batch of petitions challenging the SIR process in the poll-bound state.

{ SUPREME COURT }

See the strain and stress going on for ordinary people. Over one crore (10mn) people have been issued notices... we are going to pass some orders

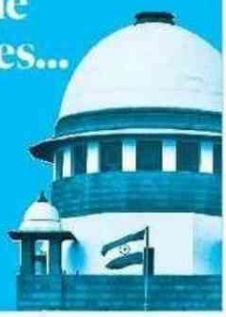

Taking note of concerns raised by petitioners over the manner in which notices citing "logical discrepancies" were issued, the court directed ECI to publish the list of persons to whom such notices have been sent. These lists must be displayed at panchayat and block offices to ensure transparency.

The bench recorded that around 1.25 crore (12.5 million) notices had been issued flagging discrepancies such as spelling variations in names, low age gap between parents and children, and instances where parents were shown as having more than six children.

To reduce hardship, the court clarified that affected voters would be entitled to submit documents or objections through authorised agents, including Booth Level Agents (BLAs), appointed through a written authorisation bearing a signature or thumb impression.

Responding to apprehensions that voters were being compelled to travel long distances, the bench directed that offices for submission of documents and objections be set up at panchayat bhavans or block offices. If documents were found unsatisfactory, election officials were directed to grant an opportunity of hearing to people, which could also be attended by the authorised agent.

Additionally, the court ordered officials to issue a receipt or certification acknowledging submission of documents or conduct of hearings, observing that this would serve as proof for voters that they had complied with the process.

On its part, the state government was directed to ensure

continued on →9

Hindustan Times

BJP tampered with rolls under SIR: Cong

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: The Congress on Monday accused the top BJP leadership of orchestrating large-scale manipulation of Rajasthan's voter lists under the special intensive revision (SIR) process. The party alleged that such manipulation predominated in assembly seats the Congress won in the last assembly elections.

Rajasthan Congress president Govind Singh Dotasra and leader of opposition Tikaram Jully addressed a press conference at the All India Congress Committee (AICC) headquarters in Delhi.

Dotasra alleged that the SIR exercise proceeded smoothly until January 3, after which a "secret plan" took effect. He claimed BJP national general secretary (organisation) BL Santhosh held a meeting in Jaipur on January 3, where the "plan" hatched.

Dotasra further alleged that the BJP carried out the operation between January 3 and January 13, working behind the scenes. "Fake computerised forms were printed assembly-wise. After Amit Shah's visit, BJP MLAs and candidates were called and given pen drives. From the evening of January 13 to January 15, thousands of forms—10,000 to 20,000 in some constituencies—were submitted to delete voter names," he alleged.

Assembly segments where the Congress won received specific targeting, Dotasra alleged, with forms submitted to delete names of voters from particular sections. He also alleged that forged signatures of booth level agents (BLAs) appeared on them.

"In my own assembly constituency, over 2,000 fake forms were brought, but the sub-divisional magistrate (SDM) refused to accept them. BLAs themselves said the signatures were forged," he claimed.

The state Congress president alleged that thousands of forms reached districts despite clear instructions from chief electoral officer Naveen Mahajan against bulk submissions. He claimed 13,882 forms arrived in Jhunjhunu, 16,276 in Mandawa and 1,478 in Khetri, with around 140,000 registered till January 15. "BJP BLAs are now saying they never signed these forms," he added.

Dotasra also alleged that BJP leaders pressured booth level officers (BLOs) to share OTPs for fake additions and deletions. "I can provide proof of BLOs being asked for OTPs," he alleged. He urged officials to resist political pressure, act strictly per law, and called on Congress workers to stay vigilant and monitor SIR proceedings at the SDM level.

Leader of opposition Tikaram Jully demanded a forensic investigation into the alleged fake forms. He claimed all forms appeared printed at a single, centralised location, then distributed through BJP leaders, MLAs, candidates and ministers to SDM offices. "The Election Commission and the Supreme Court must order a forensic probe to identify where these forms were printed and who supplied them," Jully said.

Govind Singh Dotasra and Tikaram Jully at the AICC headquarters in Delhi on Monday. HT PHOTO

Jully highlighted that on January 9, BJP's 126 BLAs submitted applications to delete just four names, but by January 16, 2,133 BJP BLAs filed applications seeking deletion of 18,896 names. "What changed overnight after Shah's visit that deletion applications ran into thousands?" he asked. He alleged agencies prepared computerised forms on a large scale.

Many deletion forms lacked signatures or mobile numbers, Jully noted, questioning their bulk acceptance. The Congress would file FIRs in fraud cases and approach courts over the "SIR manipulation", he said. At least 10 BJP BLAs submitted written statements claiming forms filed fraudulently in their names.

Jully questioned the basis of extending the SIR timeline when no SDM, collector or election official sought more time. He alleged BLOs and teachers faced transfers for refusing illegal demands, with cancellations following Congress objections.

He called the exercise a "Congress Voter Removal (CVR) campaign", saying the BJP resorted to such tactics fearing electoral defeat.

Delays in panchayat and urban local body elections, plus SIR use, formed a broader strategy to weaken Rajasthan's democratic processes, Jully alleged.

Jully issued a stern warning: the Congress would not tolerate voter list forgery. The party would ensure forgery cases registered and cautioned officials against political pressure.

"Governments may come and go, but the law will take its own course. We will fight this battle from the streets to the Supreme Court," he said.

Congress figures showed that on the final day for claims and objections, BJP's 2,133 BLAs submitted 18,896 deletion applications and 291 for additions. Congress's 110 BLAs filed just two deletions and 185 additions.

State minister Gautam Dak dismissed the Congress allegations over the special intensive revision (SIR) of voter lists. He said the party sought controversy amid absent real issues, with the entire SIR process transparent. The Election Commission published the list and provided a mechanism for claims and objections.

"All the allegations levelled by the Congress are baseless and reflect its frustrated mindset. It has become a habit of the Congress to spread lies."

Dak noted that the Election Commission as an independent constitutional body takes decisions on timeline extensions solely at its discretion, free of political pressure.

"No final deletions have occurred yet—only objections are recorded at this stage. A final decision will be taken after due verification. Voters whose names face wrongful removal can submit documents for restoration," he said.

Dak added that had the Congress raised objections after the publication of the final voter list, it would have been understandable, as presently, only the preliminary process is underway.

My forged signature used for 190 deletions from poll rolls: BJP BLA

Vijay Mathrani
letters@hindustantimes.com

BARMER: Ruga Ram, a BJP booth-level agent (BLA) from the Chohtan assembly constituency, has accused unknown persons of using forged signatures in his name to seek deletion of 190 voters from the electoral rolls.

Ram, who has served as a booth agent for nearly 15 years, said this was the first time such an incident had occurred in his gram panchayat.

"Two of the deleted voters belong to my own family, while the majority are from a minority community," said Ram, BLA from Booth No. 247 in the Sedwa subdivision.

According to Ram, Form-7 applications for deletion of 190 voters were submitted to the returning officer using fake signatures attributed to him. "When I tried to contact the concerned booth level officer (BLO) to verify the matter, my calls went unanswered. After villagers gathered and discussed the issue, I clarified that the signatures were not mine," Ram said.

Terming the entire exercise a case of fraud, he said he and the villagers will go to the police to lodge a complaint.

Baytu MLA Harish Choudhary said that the allegations made by BJP's own booth-level agents expose the seriousness of the issue. He claimed that several Form-7 applications linked to BJP's BLA-2 agents were found suspicious, with the agents themselves denying that the forms carried their genuine signatures. Choudhary alleged that as per election rules, a BLA-2 can submit a maximum of 10 Form-7 applications in a day, but in Barmer, hundreds of forms were submitted in bulk, which he described as a clear violation of norms.

BJP BOOTH-LEVEL AGENT RUGA RAM CLAIMED MOST OF DELETIONS WERE FROM A MINORITY COMMUNITY WHILE TWO BELONGED TO HIS OWN FAMILY

Choudhary further alleged that despite the seriousness of the matter, the district administration has not initiated any suo motu action or registered FIRs against those responsible. He accused the BJP of undermining democratic processes and said the constitutional right to vote cannot be taken away through fraudulent means.

He also alleged that the SIR process is being carried out in a centralised manner, with forms being filled at one location instead of at the village level. In several cases, applications were allegedly submitted to delete the names of government employees posted in the same villages. He cited instances where forged signatures of husbands were used to seek deletion of their wives' names and claimed that illiterate villagers were made to sign applications without understanding their contents.

Accusing the authorities of attempting mass deletion of voters, Choudhary said that such efforts are underway across the district, citing examples from Bishala, Janpalia, Harpalia, Arti Jalila, Bisasar, Jhadpa, and Bhanwar.

Commenting on Choudhary's allegations, BJP leader Ramesh Singh Inda said that the Congress is making baseless allegations. He clarified that only the names of those voters are being deleted who are registered at two different locations. He added that the Congress is crying foul because its own misdeeds are coming to the fore.

Election officials in Barmer were not available when contacted for a comment.

Bengal's 2.06 lakh electors linked to over 6 children: EC

Damini Nath
New Delhi, January 19

A file photo of an SIR hearing in South Kolkata

DEFENDING ITS decision to issue notices to electors flagged for "logical discrepancies" in the ongoing Special Intensive Revision (SIR), the Election Commission has told the Supreme Court that 2.06 lakh electors in West Bengal had been linked to more than six children — cases which required "greater scrutiny" to ensure the mapping was correct.

As per the EC's October 27, 2025, instructions for the SIR in 12 states/UT, including West Bengal, all registered electors were to establish a link to the last intensive revision in their state/UT through either their own name or a parent's name in the previous roll. Those who could not establish a link would be asked to appear for hearings and provide additional documents to prove their eligibility, including citizenship.

The period for serving notices is on until January 31.

In its reply filed on Sunday, the EC said "certain aspects" had emerged during the SIR that required a "different approach". It said technological tools had been adopted for verification process. "ECI has to also ensure that details of citizens of West Bengal are not misused through mapping to any name where there is no proof of parent-children relationship," it said.

The EC said the Electoral Registration Officers (ERO) of Assembly constituencies had "generated notices for verification" of five types of "identified discrepancies" — a mismatch in the name of the elector as compared to the last intensive revision roll; less than 15-year age gap between elector and parent; more than 50-year age gap between elector and parent; less than 40-year age gap between elector and grandparents; and, six or more electors mapped as progeny of one person. In case of age gaps, the EC said while the age gap could be possible, it gave rise to "suspicion".

In the case of electors being flagged for being one of six or more children of the same person, the EC said: "It was noticed that in many cases electors had marked some unrelated person as their parents to establish a link to the previous SIR."

Citing the National Family Health Survey-5 of 2019-21, the EC said the average number of children in a family is two or three. Citing examples of electors linked to "unusually high numbers of children", it said two electors had been linked to 389 and 310 progeny respectively. According to the EC, 4.59 lakh electors had been linked to more than five children; 2.06 lakh to more than six children; 8,682 to more than 10 children; 50 to more than 20 children; 14 to more than 30 children; 10 to more than 40 children; 10 to more than 50 children; seven to more than 100 children; and two to more than 200 children.

"Many of such instances are scientifically impossible to entertain as valid mapping. Therefore, cases in which six or more electors have mapped/ linked themselves to one person, merits greater scrutiny as regards validity of linkage. In such cases, EROs are issuing notices to verify whether matching has been done correctly to weed out chance of fraudulent mapping," the EC said.

The EC was replying to an application filed by TMC MP Dola Sen on January 4. The SC is hearing a batch of petitions challenging the EC's June 24, 2025, order to conduct an SIR of electoral rolls.

The EC's reply marks the first instance where it has explained the process of generating notices for "logical discrepancies" flagged by a software -- which was not mentioned in its June 24, 2025 order or in the October 27, 2025 detailed instructions for the SIR in 12 states/UTs.

The EC said "there is no automated generation of notices under the SIR exercise" and "notices are generated by EROs by selecting the option for generation of notices on the ERO App". However, what the EC did not mention is that the notices are generated through a centralised software and appear on the ERO log-in for the ERO to consider, as sources involved in the process have told *The Indian Express*.

"EROs are issuing notices by signing them after application of mind based on the information available with him and as provided by the BLO [Booth Level Officer] through the BLO App with respect to mapping of entries and their linkage to the previous SIR roll of 2002," it said.

FIRST INDIA

20 January 2026

BJP conspiring to remove our voters from electoral rolls: Cong

First India Bureau

New Delhi

Congress on Monday alleged large-scale irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Rajasthan, claiming that the exercise was being misused to add bogus voters and delete names of Congress supporters. The party also demanded a forensic examination of the forms submitted in the state.

Raj Pradesh Congress Committee president Govind Singh Dotasra and Leader of Opposition in the state assembly Tika Ram Jully alleged collusion between the BJP and the Election Commission.

Cong alleged that instead of SIR, a "Congress Voter Removal" exercise was underway in Rajasthan. Jully demanded that the EC and the Supreme Court order a forensic probe to ascertain "where these were printed and who brought them here.

PCC chief Govind Singh Dotasra, Leader of Opposition Tika Ram Jully addressing a press conf at party office in New Delhi, Monday.

CONGRESS ATTACKING SIR EXERCISE EVEN BEFORE PRELIMINARY STAGE IS OVER: GAUTAM KUMAR DAK

Rajasthan Cooperative Minister Gautam Kumar Dak on Monday accused the Congress of deliberately misleading public over the Special Intensive Revision of electoral rolls in the state. He asserted that the process was transparent and was being carried out strictly under the supervision of the Election Commission. Talking to reporters after a grievance redressal programme at the BJP's state headquarters in Jaipur, Dak said the opposition was raising objections to the Special Intensive Revision (SIR) exercise even before the completion of its preliminary stage. "No final deletion of names has taken place so far. Only claims and objections are being invited, and every case will be examined as per procedure," he said. The minister clarified that anyone who felt their name has been wrongly objected to could submit documents for verification and have it restored after scrutiny. Decisions related to extension of dates or other procedural aspects rest solely on the EC, he added.

दैनिक भास्कर डूंगरपुर भास्कर 20-01-2026

मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में मुस्लिम युवा संगठन का ज्ञापन

सीमलवाड़ा| मुस्लिम युवा संगठन ब्लॉक सीमलवाड़ा द्वारा निर्वाचन नामावली में कथित रूप से गलत तरीके से नाम हटाए जाने के विरोध में उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा विवेक गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने निर्वाचन क्षेत्र चौरासी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई है। ज्ञापन में बताया कि कुछ लोगों की ओर से बीएलओ पर दबाव बनाकर जबरन मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि बीएलओ को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन दबाव में आकर किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से नाम काटता है तो संविधान के दायरे में रहकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल गनी शेख, सलाउद्दीन फुमती और सादिक खेराडा के नेतृत्व में आरिफ इरफान, तल्हा पटेल, शाहजाद पटेल, सलीम टीटोईया, आदिल मोडासिया, जीशान डमरी, शोएब मेघरजा आदि उपस्थित रहे।

दैनिक नवज्योति Banswara Dungarpur - 20 Jan 2026 - Page 12

मतदाताओं के गलत तरीके से नाम हटाने का विरोध

मुस्लिम सामाजिक संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

सीमलवाड़ा। विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2026 के अंतर्गत चल रहे मतदाता सूची सत्यापन कार्य के दौरान चौरासी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नामावली से नाम हटाने को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसी संबंध में सोमवार को कस्बे में मुस्लिम सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एवं समाजसेवियों ने उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कुछ लोगों द्वारा मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों पर दबाव बनाकर मतदाता सूची से नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

आरोप है कि इन तत्वों द्वारा आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है तथा समुदाय विशेष के लोगों के नाम काटने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को अवगत कराया कि यदि असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से मतदाता सूची में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं बिना किसी दबाव के कार्यवाही करने की मांग की गई।यह ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल गनी शेख, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सलाउद्दीन फूमती एवं ब्लॉक अध्यक्ष सादिक खेराडा के नेतृत्व में सौंपा गया। इस अवसर पर आरिफ शेख, इरफान खेराडा, तल्लआ पटेल, शहजाद पटेल, सलीम टिंटोइया, आदिल मोड़सिया, जिशान डमरी, शोयब मेंगरजा, इस्माइल छापनोर, भिखा सूई, हफीज खेराडा, जुल्फिकार बंगा, उस्मान शा, रियाज हुसैन, मोइनुद्दीन शा, शहजाद शाह, साबिर शाह, अरहान शाह, निसार खान सहित अनेक समाजसेवी उपस्थित रहे। समाजजनों ने प्रशासन से आग्रह किया कि लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा की जाए तथा किसी भी प्रकार के दबाव में आकर नाम हटाने जैसी कार्यवाही नहीं की जाए।

सीमलवाड़ा। उपखंड अधिकारी गुर्जर को ज्ञपन सौंपते हुए मुस्लिम संगठन पदाधिकारी। गुणवंत कलाल

बीएलओ पर नाम काटने का दबाव बनाने का आरोप, सौंपा ज्ञापन

सीमलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। चौरासी क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की निर्वाचन नामावली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बीएलओ पर नाम कटवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उपखंड अधिकारी को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल गनी शेख, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सलाउद्दीन फूमती एवं ब्लॉक अध्यक्ष सादिक खेराडा के नेतृत्व में आरिफ शेख, इरफान खेराडा, तल्लआ पटेल, शहजाद पटेल, सलीम टिंटोइया, आदिल मोड़सिया, जिशान डम री, शोयब में गरजा, इस्माइल छापनोर, भिखा सूई, हफीज खेराडा, जुल्फिकार बंगा, उस्मान शा, रियाज हुसैन, मोइनुद्दीन शा, शहजाद शाह, साबिर शाह, अरहान शाह, निसार खान आदि समाज सेवी उपस्थित रहे।

फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप, नियम विरुद्ध आवेदनों पर कार्रवाई की मांग

मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप

कांग्रेस ने उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टोडारायसिंह ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी टोंक के नाम सहायक निर्वाचन अधिकारी (उपखण्ड टोडारायसिंह) के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर फर्जी व मनगढ़ंत प्रपत्र-7 भरकर निर्वाचन कार्यालय मालपुरा में जमा कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट एम. इस्लाम ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावे व आपत्तियां ली जा रही हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर झूठे प्रपत्र भरकर निर्दोष नागरिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 297 विधानसभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह में एक व्यक्ति द्वारा नजीर खारईस अहमद, मोहम्मद नफीस, शरीफ अहमद, सायमा कनीज और रफीका बानो के नाम अन्यत्र हस्तांतरण दर्शाते हुए प्रपत्र-7 जमा कराए गए, जबकि ये सभी वर्तमान में टोडारायसिंह के वार्ड संख्या 17 में ही निवासरत हैं।

इसी तरह बूथ संख्या 295 में भी 25-30 व्यक्तियों के प्रपत्र-7 भरकर जमा कराने का आरोप लगाया गया है, जबकि संबंधित मतदाता टोडारायसिंह कस्बे के निवासी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना समुचित जांच के ऐसे प्रपत्र बीएलओ को प्रेषित किए जा रहे हैं, जो संदेहास्पद है और विभागीय लापरवाही को दर्शाता है।

देवली. शहर में कांग्रेस समर्थित तथा एक विशेष जाति वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने फॉर्म-7 भरकर जीवित और स्थानीय निवासियों के नामों पर आपत्तियां दर्ज कर उन्हें सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधिसम्मत और न्यायसंगत नहीं है।

कांग्रेस कमेटी ने बताया कि ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी की गई। इसके बावजूद कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां लगाकर हटाने का प्रयास किया गया। पार्टी का आरोप है कि राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 12 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था और दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, इसके बाद भी सैकड़ों फॉर्म-7 जमा कराए गए, जो नियमों के विपरीत हैं।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष महादेव मीणा, सत्यनारायण सरसडी, सत्यनारायण बूलिया, भीमराज जैन, रमेश गोयल, टीकमचंद सेन, शम्मी रंगरेज, सद्दाम, पंकज नथैया, कैलाश राजकोट, राहुल सुवालका, मुकेश गर्ग, महेंद्र बैरवा, अमन रंगरेज सहित शहर और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के मतदाता उपस्थित रहे।

देवली. उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेसजन।

प्रक्रिया पर उठाया सवाल

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई फॉर्म-7 में आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर तक नहीं हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न होता है। इससे आगामी चुनावों की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। कांग्रेस कमेटी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखने तथा नियम विरुद्ध जमा कराए गए फॉर्म-7 की संकलित सूची कांग्रेस संगठन को उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही ऐसे आवेदनों पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेने की अपील की गई है।

पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ओर से बीएलओ पर दबाव बनाकर साजिश रची जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है और निर्वाचन विभाग व प्रशासन को इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।

दैनिक भास्कर
बहरोड़/कोटपूतली भास्कर 20-01-2026

आक्रोश • कांग्रेस समर्थक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने का आरोप, विरोध में ज्ञापन सौंपा

एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

भास्कर न्यूज | बानसूर

विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कथित रूप से गलत और अवैध तरीके से काटे जाने के विरोध में सोमवार को पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अनुराग हरित को ज्ञापन सौंपा।

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फार्म नंबर 7 को गलत मंशा से और अवैध रूप से एसडीएम कार्यालय में जमा कराकर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया गया। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार के नेता के प्रदेश में आने के बाद अचानक निर्देश बदल दिए जाते हैं और तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो बार-बार तारीख बढ़ाने का औचित्य क्या है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हजारों की संख्या में फार्म नंबर 7 जमा कराए जा रहे हैं, ताकि द्वेषपूर्ण भावना से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के समर्थकों के वोट काटे जा सके। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार का यह सुनियोजित अभियान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए तो जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। बिना ठोस जांच के किसी भी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए।

बानसूर | पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में धरना देते कार्यकर्ता।

निष्पक्ष जांच व गलत तरीके से काटे गए मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग

धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच और गलत तरीके से काटे गए मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशासन ने जल्द ही इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर, राजेंद्र रैगर, रणवीर यादव, खेमचंद गुर्जर, धर्मवीर रावत, मामचंद रावत, मुकेश सैनी, पूर्व सरपंच रामवतार मीणा, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन माडाराम गुर्जर, भोमाराम गुर्जर, दिनेश यादव, कुलदीप सैनी, योगेश पलसाना, महेन्द्र गुर्जर, डॉ. नरेश सैन, रजनीश पुरोहित, सूबेसिंह अवाना, भूपसिंह सुरेला, एडवोकेट शिवचरण रावत, राहुल आर्य, सुरेश मीणा, रणवीर डोई राजेन्द्र कुमार, मुकेश देवी, महेश गुर्जर, हरिराम धाकड़, यादराम रावत, प्रदीप यादव एडवोकेट सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक आईआईसीडीईएम-2026 की मेजबानी करेगा

इस सम्मेलन 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित यह तीन-दिवसीय सम्मेलन 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। आईआईडीईएम-2026 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन बनने जा रहा है। विश्व भर के 70 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और चुनावी क्षेत्र के अकादमिक और व्यावहारिक विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी 21 जनवरी, 2026 को उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और कार्यवाही को हरी झंडी दिखाएंगे। तीन-दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन निकाय (ईएमबी) के सामान्य एवं विशेष सत्र शामिल हैं, जिनमें उद्घाटन सत्र, चुनाव प्रबंधन निकाय के नेताओं का पूर्ण सत्र, चुनाव प्रबंधन निकाय के कार्य समूह की बैठकें, साथ ही वैश्विक चुनावी मुद्दों, आदर्श अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रणालियों पर केंद्रित विषयगत सत्र शामिल हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के नेतृत्व में और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञों के सहयोग से गठित कुल 36 विषयगत समूह सम्मेलन के दौरान गहन विचार-विमर्श में योगदान देंगे। इन चर्चाओं में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) और आईआई एमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी होगी। भारत निर्वाचन आयोग विश्वभर में चुनाव प्रबंधन निकाय के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करेगा।

3 दिनों में 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 सत्र आयोजित किए जाएंगे

बायतु विधायक, सांसद सहित कांग्रेस के नेता रहे मौजूद

मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने बाड़मेर व चौहटन में सौंपा ज्ञापन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बाड़मेर /चौहटन पत्रिका. राजस्थान में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के दौरान सत्यापित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता एवं बायतु विधायक नेता हरीश चौधरी, सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, पूर्व मंत्री गफूर अहमद व पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने जिला कलक्टर टीना डाबी व चौहटन में रिटर्निंग अधिकारी चौहटन को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि एसआइआर प्रक्रिया के तहत कई स्थानों पर फॉर्म-07 बिना संबंधित मतदाता को सूचना दिए और आवश्यक दस्तावेजों की जांच किए बिना भरे गए। हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि निरक्षर महिलाओं के कथित झूठे हस्ताक्षर कराए गए, पति-पत्नी के नाम अलग-अलग काटे गए और कुछ सत्यापित मतदाताओं को अन्यत्र स्थानांतरित दिखाया गया। उन्होंने इसे पंचायत स्तर पर योजनाबद्ध साजिश करार दिया, जिससे आम नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

बाड़मेर में एसआइआर में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि एसआइआर के नाम पर भोले-भाले लोगों के नाम फर्जी तरीके से हटाकर उन्हें मतदान से वंचित करने की भाजपा की मंशा स्पष्ट हो रही है। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है।

प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से फॉर्म-07 से दर्ज आपत्तियों की विशेष और निष्पक्ष जांच, मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। हरीश चौधरी ने चेतावनी दी कि संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर किसी भी पक्ष की एकतरफा कार्यवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य नहीं है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, पीसीसी सदस्य ठाकाराम माली, सेड़वा प्रधान रमेश भील, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तिलोक पोटलिया व दीन मोहम्मद, उपप्रधान शुजा मोहम्मद व रूगनाथ राम विश्नोई सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।

नाम हटाने के मानकों का नहीं किया पालन: कांग्रेस

बायतु. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

इस संबंध में सोमवार को बायतु विधायक हरीश चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बायतु उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रस्तुत कई आवेदनों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। आरोप हैं कि बिना स्थलीय सत्यापन, संबंधित मतदाता को सूचना दिए बिना तथा आवश्यक दस्तावेजों की समुचित जांच किए बिना नाम विलोपित कर दिए गए।

कुछ मामलों में निरक्षर महिलाओं के कथित रूप से झूठे हस्ताक्षर कराए जाने तथा पति-पत्नी के नाम अलग-अलग काटे जाने जैसी गंभीर शिकायतें भी सामने आई हैं। विधायक हरीश चौधरी ने

बायतु में ज्ञापन सौंपता कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल।

कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची से नाम हटाने से पूर्व पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी मतदाता का संवैधानिक मताधिकार प्रभावित न हो। उन्होंने सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा गलत तरीके से हटाए गए नामों को पुनः सूची में जोड़ने की मांग की।

साथ ही भविष्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता, कानूनसम्मत तरीके और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संपन्न कराने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर बायतु प्रधान सिमरथाराम चौधरी, गिड़ा पूर्व प्रधान लक्ष्मण राम डेलू, गिड़ा मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश घाट, परेऊ ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत भाटिया, संतरा मंडल अध्यक्ष तेजाराम मेघवाल, दावद खान सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर

धौलपुर 20-01-2026

मतदाता सूचियों से नाम हटाने और आपत्तियों के विरोध में दिया ज्ञापन

बाड़ी | चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहे मतदाता सूचियां के गहन पुनरीक्षण अभियान में आपत्तियों के नाम पर हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी ने आपत्ति के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा और मामले में भ्रम,भय और असंतोष की स्थिति को खत्म करने की मांग की।

कांग्रेस सेवादल के जिला महासचिव अभिषेक के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर मतदाता सूची को शुद्ध पारदर्शी बनाने के लिए है। लेकिन खेद का विषय है कि इस प्रक्रिया की आड़ में कुछ असामाजिक और स्वार्थी तत्व वैध जीवित और नियमित रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर फर्जी आपत्ति लगा रहे है। इस प्रकार की आपत्तियों के कारण न केवल आम नागरिकों का संवैधानिक मताधिकार प्रभावित हो रहा है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में मतदाताओं को जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनसे भ्रम,भय और असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तीन दिन से प्रदर्शन कर रही है।

सेवादल के पदाधिकारी परवेज पठान,निजामुद्दीन खां,शब्बीर बाबा,मोहम्मद शकील,राकेश अजर आदि ने बताया कि प्रशासन मतदाता सूची से नाम हटाने से पूर्व आपत्तियों की गहन जांच और भौतिक सत्यापन करें,फर्जी एवं दुर्भाग्यपूर्ण आपत्तियां लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। किसी भी वैध मतदाता का नाम बिना उचित सुनवाई और ठोस प्रमाण के नहीं हटाया जाए। उक्त मामले की ठोस जांच हो और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव के नेतृत्व में दिया ज्ञापन

खबरों की दुनिया

धौलपुर । बाड़ी में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान में आपत्तियों के नाम पर हो रही कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस सेवादल के जिला महासचिव अभिषेक यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। पूर्व ब्लाक अध्यक्ष शकील कुरैशी कांग्रेस नेता निजामुद्दीन खान कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवेश पठान एडवोकेट राकेश अजय पार्षद आकाश यादव सतीश खेमरिया साबिर कुरेशी दुर्गा जाटव आदि लोग मौजूद रहे।

कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव अभिषेक यादव के नेतृत्व में दिया ज्ञापन

जयपुर टाइम्स

धौलपुर(निस)। बाडी में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान में आपत्तियों के नाम पर हो रही कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फर्जीवाड़े को रोकने और भ्रम, भय व असंतोष की स्थिति समाप्त करने की मांग की। कांग्रेस सेवादल के जिला महासचिव अभिषेक यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। हालांकि कुछ असामाजिक और स्वार्थी तत्व इस प्रक्रिया की आड़ में वैध, जीवित और नियमित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी आपत्तियां लगा रहे हैं। पूर्व ब्लाक अध्यक्ष शकील कुरैशी, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन खान, कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवेश पठान, एडवोकेट राकेश, अजय पार्षद, आकाश यादव, सतीश खेमरिया, साबिर कुरेशी, दुर्गा जाटव आदि लोग मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर 20.01.2026

तारानगर. एसडीएम को ज्ञापन देते विधायक बुड़ानिया व अन्य।

एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई, ज्ञापन दिया

भास्कर न्यूज | तारानगर

एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को विधायक नरेन्द्र बुडानिया के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष वेदप्रकाश सहारण व मदन पांडिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक बुडानिया ने कहा कि हमने एसआईआर अभियान में प्रशासन का सहयोग किया। वहीं भाजपा के लोगों ने गलत तरीके से वोट काटने का काम किया है, जो लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन कांग्रेस कभी भी ऐसा नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अधिकारियों व बीएलओ पर दबाव बनाकर कांग्रेस समर्थित विशेष समुदाय के लोगों के नाम गलत तरीके से कटाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के बाद विधायक के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एसडीएम राजेंद्र कुमार को ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजय कस्वा, मुंशी तेली, हरिसिंह बेनीवाल, उमाशंकर शर्मा, बाबू हुसैन कुरैशी, किशोरसिंह राजवी, कृष्ण कुमार सहारण, विमला कालवा, अभिषेक बुड़ानिया, जीतराम जांदू, रामस्वरूप झाझड़िया, सहदेव भाटी, माणकचंद बैद, पन्नालाल कस्वा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राजस्थाान पत्रिका 20.01.2026

मतदाता सूची से नाम हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चूरू. एसआइआर के तहत फर्जी तरीके से कार्य कर मतदाताओं के मतदाता सूचियों ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप में सोमवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्टर को सौंपा। विधायक बुडानिया ने बताया कि राज्य में एसआइआर का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन तारानगर में इस कार्य में अनियमितता बरती जा रही हैं।

चूरू. कलक्टर को ज्ञापन देने जाते विधायक बुडानिया व कार्यकर्ता ।

उन्होंने बताया कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार फार्म नं. 7 के संख्या 929 थी, लेकिन 15 जनवरी शाम के समय इस कार्यालय में फार्म नं. 7 जी कम्प्यूटराइज्ड थे जिनकी संख्या करीब 6-7 हजार हैं जो अवैध तरीके से जमा करवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी बीएलओ को बुलाकर देर रात 12 बजे तक उन 67 हजार फार्मों में अंकित मतदाताओं के नाम हटवाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बीएलए-2 एक दिन में मात्र 10 फार्म जमा करवा सकता हैं। ज्ञापन में एक एक बीएलए-2 की ओर से 150 से 300 तक की संख्या में एक दिन में फार्म जमा करवाएं जाने का आरोप लगाया हैं। ज्ञापन के माध्यम से फर्जी तरीके से जमा फार्म संख्या 7 को जांच की करने, फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म जमा करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, फर्जीवाड़ा करने वाले पर निर्वाचन नियमों के तहत कार्य की जाने की मांग की और कहा कि कार्रवाई कर इस तरह की भविष्य में नहीं हो इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए।

इस अवसर पर तारानगर प्रधान संजय कस्वां, उमाशंकर शर्मा, अभिषेक बुडानिया, मोहर सिंह, संतोष मेहरा, शिमला, हरि सिंह, संदीप नेवलिया, वेदप्रकाश, रामप्रताप स्वामी, पवन योगी, नरेन्द्र, विमला कालवा, जय सिंह , मो.रसीद, हनुमानसिंह कस्वां आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आनन फानन में फार्म वापस मंगवाए

विधायक ने बताया कि कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारियों की ओर से बीएलओ से फार्म वापस मंगवाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़ा षड्यंत्र कर फर्जी तरीके से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास किया गया हैं।

दै नवज्योति 20.012026

तारानगर में फर्जी वोट हटाने का आरोप, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

न्यूज सर्विस/ नवज्योति,
चूरू। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत फार्म संख्या सात में फर्जी हस्ताक्षर कर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के वोट हटवाने के आरोपों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक नरेन्द्र बुड़ानिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले विधायक निवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। विधायक बुड़ानिया ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने

आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के वोट काटने की साजिश रची जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाजपा कार्यकर्ता बीएलओ को धमका रहे हैं कि उन्हें पार्टी का काम करना पड़ेगा और वही करना होगा जो वे चाहेंगे। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजय कस्वां, अभिषेक बुड़ानिया, ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सहारण, मदन पांडया, मोहरसिंह ज्याणी, उमाशंकर शर्मा, प्रकाश मेघवाल, हरिसिंह बेनिवाल, भागीरथ भामी, बाबू हुसैन कुरैशी, मुंशी खां, मोहरसिंह धाणक, दिनेश शर्मा, मानसिंह सैनी, कृष्ण सहारण, हर्ष कुमार, पप्पू गोस्वामी, संतलाल नाई, अजीज खान सहित कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

मनरेगा को लेकर प्रदर्शन, मजबूत करने की उठाई मांग

न्यूज सर्विस/ नवज्योति,
झुंझुनूं। कांग्रेस नेता अमित ओला ने मनरेगा को कमजोर किए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों की रोजी-रोटी का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन सरकार इसे कमजोर कर मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला कर रही है। यह नीति लाखों गांवों और करोड़ों श्रमिकों के हक की खुली लूट है। इसी जनविरोधी नीति के खिलाफ झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बासनानग के आम चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने भाग लेकर मनरेगा को मजबूत करने की मांग

उठाई। अमित ओला ने कहा कि मनरेगा सिर्फ रोजगार की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार की लापरवाही और बजट कटौती के कारण मजदूरों को समय पर काम और मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से मनरेगा को पूरी तरह लागू करने, मजदूरी समय पर देने और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी की मांग की। विरोध शांतिपूर्ण रहा और ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर गीडानिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमेर सिंह महला, बाकरा सरपंच राजेंद्र चाहर, बासनानग सरपंच जगदीश एवं देरवाला की पूर्व सरपंच रेखा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दै आस पास 20.01.2026

सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन

तारानगर। तारानगर में एसआईआर के तहत फर्जी तरीके से फार्म संख्या सात में फर्जी हस्ताक्षर कर वोट हटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक नरेन्द्र बुड़ानिया के नेतृत्व में जिला कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इससे पहले विधायक निवास पर विधायक बुड़ानिया के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई ततपश्चात सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे जहाँ उन्होंने उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। विधायक बुड़ानिया ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा भाजपा के लोग प्रजातंत्र कमजोर करने की कोशिश कर रहे है। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के वोट काटने की कोशिश की जा रही है जो सरासर गलत है हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि भाजपा के लोग बीएलओ को धमका रहे है कि आपको पार्टी का काम करना पड़ेगा हम जो चाहेंगे वो ही होगा अन्यथा आपका स्थानांतरण कर दूर भेज देंगे। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजय कस्वां, अभिषेक बुड़ानिया, ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सहारण, मदन पांडया, मोहरसिँह ज्याणी, उमाशंकर शर्मा, प्रकाश मेघवाल, हरिसिंह बेनिवाल, भागीरथ भामी, बाबू हुसैन कुरैशी, मुंशी खां, मोहर सिँह धाणक, दिनेश शर्मा, मानसिंह सैनी, कृष्ण सहारण, हर्ष कुमार, पप्पू गोस्वामी, संतलाल नाई, अजीज खान सहित कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जयपुर टाइम्स 20.01.2026

उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा मांगपत्र

जयपुर टाइम्स

तारानगर(निस)। तारानगर में एसआईआर के तहत फर्जी तरीके से फार्म संख्या सात में फर्जी हस्ताक्षर कर वोट हटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही करने की मांग को लेकर तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक नरेन्द्र बुड़ानिया के नेतृत्व में जिला कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इससे पहले विधायक निवास पर विधायक बुड़ानिया के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसके बाद सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे जहाँ उन्होंने उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। विधायक बुड़ानिया ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा भाजपा के लोग प्रजातंत्र कमजोर करने की कोशिश कर रहे है। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के वोट काटने की कोशिश की जा रही है जो सरासर गलत है हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि भाजपा के लोग बीएलओ को धमका रहे कि आपको पार्टी का काम करना पड़ेगा हम जो चाहेंगे वो ही होगा। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजय कस्वां, अभिषेक बुड़ानिया, ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सहारण, मदन पांडया, मोहरसिंह ज्याणी, उमाशंकर शर्मा, प्रकाश मेघवाल, हरिसिंह चौनवाल, भागीरथ भामी, बाबू हुसैन कुरैशी, मुंशी खां, मोहर सिंह धाणक, दिनेश शर्मा, मानसिंह सैनी, कृष्ण सहारण, हर्ष कुमार, पप्पू गोस्वामी, संतलाल नाई, अजीज खान सहित कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जनमानस शेखावाटी न्यून 20.01.2026

तारानगर विधायक ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंप ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

जनमानस शेखावाटी न्यूज

चूरू: चूरू में तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम चूरू पहुंचकर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों से फर्जी तरीके से नाम हटाने के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में विधायक बुड़ानिया ने बताया कि राज्य में एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन तारानगर में इसमें अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार फॉर्म नंबर 7 की संख्या 929 थी, जो 15 जनवरी की शाम तक कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत फॉर्म नंबर 7जी के रूप में बढ़कर करीब 6-7 हजार हो गई। ये फॉर्म अवैध तरीके से जमा करवाए गए थे।

बुड़ानिया ने आगे आरोप लगाया कि सभी बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को बुलाकर देर रात तक उन हजारों फॉर्मों में अंकित मतदाताओं के नाम हटवाने के निर्देश दिए गए थे। कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने आनन-फानन में बीएलओ से फॉर्म वापस मंगवा लिए। विधायक ने इसे एक बड़ा षड्यंत्र बताते हुए वास्तविक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटवाने का प्रयास करार दिया।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि एक बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट) एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म जमा करवा सकता है, जबकि तारानगर में एक ही बीएलए-2 द्वारा 150 से 300 तक की संख्या में फॉर्म जमा करवाए जाने का आरोप है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से फर्जी तरीके से जमा किए गए फॉर्म संख्या 7 की जांच करने, फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म जमा करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फर्जीवाड़ा करने वालों पर निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की। बुड़ानिया ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।

ज्ञापन सौंपने वालों में तारानगर प्रधान संजय कस्वां, उमाशंकर शर्मा, अभिषेक बुड़ानिया, मोहर सिंह, संतोष मेहरा, शिमला, हरि सिंह, संदीप नेवलिया, वेदप्रकाश, रामप्रताप स्वामी, पवन योगी, नरेंद्र, विमला कालवा, जय सिंह, मो. रसीद और हनुमान सिंह कस्वां सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

जिसके नाम से शिकायत उन्होंने ऑडियो में पार्टी और विधायक का आदेश होना बताया

एसआइआर : 40 साल से शहर में रह रहे रिटायर्ड आरएएस का नाम भी कटा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

उदयपुर. एसआइआर की प्रक्रिया में नाम कटने को लेकर भले ही कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी नाम कटे हैं, जो दशकों से शहर में रह रहे हैं। उदयपुर में पूर्व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सहित अनेक पदों पर सेवाएं दे चुके रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अहसान अहमद छीपा का भी नाम एसआईआर प्रक्रिया में कट गया। जब उन्होंने पड़ताल की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

रिटायर्ड आरएएस अहसान अहमद छीपा ने बताया कि वे 40 साल से उदयपुर में नौकरी कर रहे थे। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म भरकर दिए थे। जबकि, परिवार के तीन लोगों के नाम कट गए। कलक्ट्रेट के कमरा नम्बर 308 में कार्मिक से मिले, जिसने बीएलओ को 185 नाम काटने के लिए देना बताया। जिस आपत्ति से नाम काटा जाना बताया, उस पर देवाली निवासी राजकुमार नामक व्यक्ति का नाम और नम्बर लिखा था। उससे बात की तो उसने शिकायत पर अनभिज्ञता जताई।

जिम्मेदारों ने लिए बड़े नाम: जब बीएलओ से बात की तो उसने विधायक से बात करने और कलक्ट्रेट के बाबू की ओर से सूची देना बताया। कार्मिक ने भी पार्टी कार्यालय और विधायक की ओर से नाम काटे जाने की सूची देना बताया गया। विधायक से बात की तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जता दी। इसकी शिकायत संभागीय आयुक्त और एडीएम सिटी को दी गई है।

वोटर लिस्ट जिसमें रिटायर्ड आरएएस सहित परिवार के लोगों के नाम नहीं है।

इधर, कांग्रेस का प्रदर्शन जारी

एसआइआर के मुद्दे पर सोमवार को शहर अध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ की अगुवाई में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी रहा। विधायक पर मतदाता सूची से नाम कटाने समेत कई आरोप लगाते हुए पुतला जलाया गया। जिला प्रशासन से जांच की भी मांग की। आरोप है कि एसआइआर में वास्तविक मतदाताओं के नाम कटवाए गए। प्रदर्शन में महासचिव पंकज शर्मा, दिनेश दवे मौजूद थे।

Scanned with OKEN Scanner